संपादकीय जागरण

रविवार, 3 दिसंबर, 2017 : मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा वि. 2074

आत्ममुग्धता पतन को आमंत्रण देती है

आंतरिक लोकतंत्र का दिखावा

गुजरात चुनाव के पहले एक और चुनाव होने जा रहा है, लेकिन यदि उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही और उसके प्रति कहीं कोई उत्सुकता नहीं तो इसीलिए कि हर कोई उसके नतीजे से अच्छी तरह परिचित है। यह चुनाव है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का। इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले दिनों नामांकन की अधिसूचना जारी हो गई, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। कोई आवेदन पत्र तक लेने की भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इस पर हैरत नहीं, क्योंकि आखिर कांग्रेस में कोई भी नेता राहुल गांधी को चुनौती देने का साहस क्यों जुटाएगा? इसकी आगे भी संभावना इसलिए नहीं है, क्योंकि इस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले पार्टी के एक कार्यकर्ता शहजाद पूनावाला को कांग्रेस के नेता कांग्रेसी मानने से ही इन्कार कर रहे हैं। पता नहीं शहजाद पूनावाला ने किस मकसद से कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए? उन्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए था कि इस मसले पर सवाल उठाना बेकार है और इस कथित अपराध में वह किनारे किए जा सकते हैं। हो सकता है कि उनका मकसद केवल चर्चा में आना और प्रचार पाना हो, लेकिन यह सवाल तो अपनी जगह है ही कि जब राहुल गांधी के अलावा अन्य किसी के अध्यक्ष बनने की दूर-दूर तक कहीं कोई गुंजाइश नहीं तब फिर चुनाव का दिखावा क्यों किया जा रहा है? आखिर ऐसे चुनाव का क्या मतलब जिसमें केवल एक ही प्रत्याशी हो? क्या यह विचित्र नहीं कि चुनाव प्रक्रिया को गंभीरता प्रदान करने के लिए राहुल गांधी न केवल नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, बल्कि फिर अन्य किसी के अपना नामांकन वापस लेने की प्रतीक्षा भी करेंगे?

कांग्रेस की यह दुविधा समझी जा सकती है कि वह अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि को ही राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की घोषणा करे या फिर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख को, लेकिन यह समझना कठिन है कि ऐसी चुनाव प्रक्रिया को आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा कैसे कहा जा सकता है? यह सही है कि देश के अधिकांश राजनीतिक दलों के अध्यक्ष कुछ उसी तरह चुने जाते हैं जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी चुने जाने वाले हैं, लेकिन यह तो एक गनीमत है ही कि चंद राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जहां अध्यक्ष पद के कई दावेदार होते हैं और कई बार यह जानना कठिन होता है कि उनका अगला अध्यक्ष कौन होगा? आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में वैसा आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं है जैसा चंद राजनीतिक दलों में है? यह वह सवाल है जो कांग्रेस के नेताओं को अपने आप से करना चाहिए। दुर्भाग्य से इसके कहीं कोई आसार नहीं, क्योंकि खुद राहुल का यह मानना है कि भारत में तो ऐसा ही होता है। यह बात उन्होंने जिस अमेरिका में जाकर कही वहां ऐसा बिलकुल भी नहीं होता। सच तो यह है कि अमेरिका के साथ-साथ ब्रिटेन एवं अन्य कई लोकतांत्रिक देशों में भी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के नाम पर वैसा कोई दिखावा नहीं होता जैसा भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों में होता है।

सीबीआइ का घेरा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के तटों को रिवर फ्रंट चैनलाइजेशन के नाम पर घेरने वालों के चारों तरफ अब सीबीआइ की एंटी करप्शन ब्रांच का घेरा बन गया है। इस यूनिट ने नामजद एफआइआर को ही आधार मानते हुए आठ अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। योगी सरकार ने गठन के बाद ही रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार की जांच का एलान किया था। अप्रैल में न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आलोक सिंह की अध्यक्षता में समिति बनी। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जून में गोमतीनगर थाने में आठ अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई। इसी प्राथमिकी को आधार बनाते हुए सीबीआइ ने सिंचाई विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंताओं गुलेश चंद, एसएन शर्मा और काजिम अली सहित आठ अधिकारियों से जुड़ी जानकारियां जुटानी शुरू कर दी हैं। समझा जाता है कि जल्द ही इनके ठिकानों पर छापे डाले जा सकते हैं। इनसे मिले सुबूतों के सहारे कुछ राजनीतिक हस्तियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

गोमती नदी प्रदूषण की दुर्गंध से मुक्त होने के पहले ही भ्रष्टाचार की बदबू चारों ओर फैल गई

दरअसल राजधानी लखनऊ के बीचो-बीच से बहने वाली गोमती नदी का उद्गमस्थल हिमालयी क्षेत्र न होकर तराई के पीलीभीत जिले में है। बरसात के बाद इसमें पानी का प्रवाह कम हो जाता है। शहर के नालों का चार सौ से ज्यादा एमएलडी पानी इसे प्रदूषित करता रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए अखिलेश सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया, जिसे गोमती नदी चैनलाइजेशन परियोजना एवं गोमती नदी रिवरफ्रंट डेवलमेंट कहा गया। सिंचाई विभाग को पूरा काम दे दिया गया। इसमें अनियमितताओं की गुंजायश भरपूर थी, लिहाजा गोमती नदी प्रदूषण की दुर्गंध से मुक्त होने के पहले ही भ्रष्टाचार की बदबू चारों ओर फैल गई। बिना पानी की गोमती नदी के चैनलाइज होने से पहले ही कई करोड़ रुपया कहीं ड्रेन हो गया। देखना यह है कि सीबीआइ कितना दूध और कितना पानी अलग कर सकेगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आर्थिक विकास दर के ताजा आंकड़े नोटबंदी और जीएसटी के असर समाप्त होने के सूचक हैं?

आज का सवाल

क्या केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पोषण मिशन से देश में कुपोषण की समस्या समाप्त हो सकती है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आर्थिक मोर्चे पर अच्छे संकेत

संजय गुप्त

जीडीपी में वृद्धि दिखने के बावजूद सरकार को यह समझने की जरूरत है कि अर्थव्यवस्था को और गति देने एवं उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता बनी हुई है

पांच तिमाहियों के बाद आर्थिक विकास दर में उछाल दर्ज होना मोदी सरकार के लिए न केवल आर्थिक मोर्चे पर राहतकारी है, बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी। ऐसा इसलिए, क्योंकि गुजरात चुनाव में अन्य अनेक मसलों के साथ अर्थव्यवस्था की सेहत को भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। चूंकि जीडीपी में उछाल यह भी बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी के साथ-साथ जीएसटी के असर से भी मुक्त हो रही है इसलिए यह स्वाभाविक है कि सरकार राहत महसूस करती दिख रही है। हालांकि यह पहले से तय था कि नोटबंदी का कुछ न कुछ असर जीडीपी पर पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद आर्थिक विकास दर में गिरावट को राजनीतिक मसला बनाने की कोशिश की गई। चूंकि अर्थव्यवस्था जब नोटबंदी के असर से मुक्त हो रही थी तभी जीएसटी पर अमल शुरू हो गया और उसकी जटिलता के कारण जीडीपी पर असर पड़ा इसलिए विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस की ओर से यह कहा जाने लगा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही है। हालांकि यह भी पहले से तय था कि जब भी जीएसटी पर अमल होगा उद्योग-व्यापार जगत को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद जीएसटी का हौवा बनाने की कोशिश की गई। उसे गब्बर सिंह टैक्स तक कहा गया। जीएसटी को किस तरह सस्ती राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, यह इससे पता चलता है कि कांग्रेस ने बीते दिनों सूरत में गब्बर सिंह, सांभा, कालिया वगैरह के वेश में एक जुलूस निकाला।

आर्थिक मसलों को चुनावी मुद्दा बनाने में हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा करते समय तथ्यों को मनमाने तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। यह कहना कठिन है कि जीडीपी के ताजा आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस जीएसटी को मसला बनाने की कोशिश जारी रखेगी या बंद करेगी, लेकिन यह तय है कि सरकार और भाजपा इसे अपनी एक उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करेगी। यह स्वाभाविक भी है, लेकिन जहां यह उत्साहजनक है कि आखिरकार जीडीपी में वृद्धि का सिलसिला कायम हुआ वहीं इसके प्रति सतर्क रहने की भी आवश्यकता है कि आर्थिक वृद्धि दर में बढ़त का यह क्रम जारी रहे। यह ठीक है कि जीएसटी में सुधार की प्रक्रिया जारी है और उसके बेहतर असर भी दिखेंगे, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब जब यह कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी जैसे अल्पकालिक झटकों से मुक्त हो चुकी है तब फिर इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए कि पेट्रोलियम उत्पाद और रियल्टी सेक्टर जीएसटी के दायरे में कैसे आएं? सच तो यह है कि शराब को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए, क्योंकि इन सबको सबसे बड़े टैक्स सुधार के दायरे से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। सरकार इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि जीडीपी में वृद्धि के बावजूद निवेश के मोर्चे पर स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं। यह ठीक नहीं कि विदेशी पूंजी निवेश के साथ-साथ घरेलू उद्यमी भी पूंजी निवेश करने के लिए और इंतजार करते दिख रहे हैं। अब जब कारोबारी माहौल में सुगमता पर मुहर लग गई है तब फिर सरकार को यह देखना ही चाहिए अपेक्षित पूंजी निवेश क्यों नहीं हो रहा है? जीडीपी में वृद्धि के आंकड़ों का एक सच यह भी है कि कृषि और सेवा क्षेत्र में गिरावट के साथ अर्थव्यवस्था में निर्यात की भी भागीदारी कम दिख रही है। यह पिछली तिमाही के 1.2 फीसद के स्तर पर ही नजर आ रहा है।

अवधेश राजपूत

सरकार को जिस मोर्चे पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है वह है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र की हालत में सुधार सरकार की प्राथमिकता सूची में होना चाहिए। यह इसलिए ,क्योंकि जीडीपी के ताजा आंकड़ों में कृषि क्षेत्र में विकास दर महज 1.7 प्रतिशत ही दिख रही है। यह वृद्धि दर पिछली तिमाही से भी कम है? ऐसा क्यों है, इसके कारणों का पता करके उनका निवारण करने पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तो इसलिए कि सरकार बार-बार यह कह रही है कि वह अगले पांच सालों में किसानों की आय दोगुना करना चाहती है और दूसरे, इसलिए कि खेती पर एक बड़ी आबादी निर्भर है। आखिर कृषि क्षेत्र की मौजूदा वृद्धि दर से किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? हालांकि कृषि क्षेत्र और किसानों की हालत में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके सकारात्मक परिणाम सामने आते नहीं दिख रहे हैं। किसानों की एक बड़ी समस्या खेती की लागत बढ़ते जाना और उपज का उचित मूल्य न मिल पाना है। सरकार के नीति-नियंता इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि इस समस्या का समाधान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से भी नहीं हो पा रहा है। किसानों को लागत से कुछ अधिक मूल्य कैसे मिले, इसे सुनिश्चित करने के साथ ही कृषि क्षेत्र पर आबादी के बड़े हिस्से की निर्भरता कम करने की भी जरूरत है। इस जरूरत की पूर्ति तब होगी जब उद्योग-व्यापार जगत में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे।

यह सही है कि जीडीपी के ताजा आंकड़े सरकार को राहत देने और यह कहने का अवसर देने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर निराशा जताने का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसी के साथ वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर के अंत तक राजकोषीय घाटा पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य के 96 फीसद तक पहुंच गया था। इसके चलते चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार करने की आशंका जताई जा रही है। इस आशंका का मूल कारण सरकार का खर्च अधिक और आमदनी अनुमान से कम रहना है। इसी आशंका के चलते जीडीपी में वृद्धि के आंकड़ों के बावजूद शेयर बाजार में बढ़त के बजाय गिरावट दर्ज की गई। ध्यान रहे कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को कम कर जीडीपी के 3.2 फीसद तक लाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य पाना इसलिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कर संग्रह में कमी आ रही है। एक मुश्किल यह भी है कि कर राजस्व के साथ गैर-कर राजस्व में भी कमी आती दिख रही है। हालांकि सरकार विनिवेश के जरिये अच्छी-खासी रकम जुटाने के आश्वासन देती रही है, लेकिन विनिवेश प्रक्रिया उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही जितनी कि अपेक्षित है।

जीडीपी में वृद्धि दिखने के बावजूद सरकार को यह समझने की जरूरत है कि अर्थव्यवस्था को और गति देने एवं उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता बनी हुई है। जिस तरह जीएसटी में सुधार और बदलाव के लिए गठित समिति ने व्यापारियों के लिए समस्या बने तमाम नियम-कानूनों की पहचान कर ली है और सरकार उन्हें दूर करने के लिए तैयार दिख रही है उसी तरह उसे अर्थव्यवस्था की अन्य समस्याओं के समाधान पर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इससे ही उद्योग-व्यापार जगत को राहत मिलने के साथ ही सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मजबूत दिखेगी। दरअसल जब ऐसा होगा तभी आर्थिक मसलों पर नारेबाजी की राजनीति का सिलसिला थमेगा।

response@jagran.com

शेर और खरगोश की नई कथा

हास्य-व्यंग्य

सूर्यकुमार पांडेय

शेरों द्वारा आयोजित होने वाली पार्टी में एक हजार खरगोश आते तो उनमें से आधे ही अपने घरों को लौट पाते थे

ढेर सारे खरगोश थे। थोड़े से शेर थे। जैसा कि सदा से होता आया है, दोनों ही जंगल में रहते थे। वह जंगल था, इसलिए उसके अपने कतिपय कायदे-कानून भी थे। पहला नियम तो यह ही था कि शेरों के खानदान में शेर ही पैदा होते थे। खरगोशों के घरों में खरगोश जन्म लेते थे। शेर बड़े होकर जंगल में राज करते और जंगल के राजा कहे जाते थे। खरगोश उनकी प्रजा कहलाते थे। शेरों ने अपने लिए जंगल के इलाके बांट रखे थे। उनमें आपस में एक मौन समझौता था, इतना वन-क्षेत्र हमारा, इतना तुम्हारा। प्रत्येक पांच या दस वर्षों के बाद वे अपने वन-क्षेत्रों को आपसी समझौते के आधार पर बदल भी लिया करते थे। शेर खरगोशों की आश्वस्ति के लिए बराबर उनके बीच जाकर यह प्रचारित करते रहते थे कि जब तक हम शेरों का राज है, तुम्हें किसी बाघ या भालू से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इज्जत हमारे हाथों में है। इसे कोई दूसरा नहीं ले सकता है। वे यदा-कदा अपने मनोरंजन के लिए उन खरगोशों से पूछ लिया करते थे, 'तुम लोग भी राजा बनोगे!' इस पर खरगोशों की ओर से भी सदैव सकारात्मक प्रतिक्रिया ही मिला करती थी।

राजा कौन नहीं बनना चाहता है? उन खरगोशों के मन में भी राजा बनने के सपने होते थे। कुछ युवा खरगोश तो राजा का स्वांग बनाकर जब-तब कुलांचे मारते और सबको आनंदित करते थे। उनके परिवारों के बुजुर्ग और अनुभवी खरगोश यह देखते तो मुस्कुरा भी देते थे। खरगोश शेरों से पूछते थे, 'क्या हम लोग भी राजा बन सकते हैं?' तब शेर उनसे कहते थे, 'क्यों नहीं? तुम हमसे चुनाव लड़ो। जीत जाओ और राजा बन जाओ। आखिरकार यह सारा जंगल तुम्हारा ही तो है। इस पर असली अधिकार तो तुम्हारा ही है। हम भी तो तुम्हारे लिए ही राजा बना करते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी तुम्हारी सेवा की है। आज हम कर रहे हैं। तुममें से कोई राजा बन जाएगा, तो हम कुछ दिन आराम कर लेंगे।' बेचारे खरगोश शेरों के झांसे में आ जाते थे। वे चुनाव लड़ते थे। उनमें से कुछ हार जाते थे। अधिकांश खरगोशों की तो जमानतें तक जब्त हो जाया करती थीं। कुछ शेरों के पेट में पहुंच जाते थे। अंततः विजय शेरों की ही हुआ करती थी। वे पुनः राजा बनते थे। खरगोश प्रजा रहने के लिए अभिशप्त थे। यही उनकी नियति थी। शेरों को राज करने का नैसर्गिक और जन्मजात वरदान मिला हुआ था। उन्हें राज करने के तमाम छल-छद्म पता थे। इस तरह शेर जंगल में राज करते और जब उनको भूख लगती थी, निरीह खरगोश ही उनका आहार हुआ करते थे।

खरगोशों की नियति ही यह होती है कि वे शेरों के शिकार बनते रहें। संख्या-बल में खरगोश अधिक होते हैं, शेर कम। फिर भी जंगल में शेरों की ही चलती है। ऐसा ही कहानियों में लिखा होता है और यथार्थ में भी यही होता है। तो ऐसा ही हो रहा था। शेर मस्त थे। सर्व सुविधा संपन्न थे। माननीय थे। खरगोश त्रस्त थे। अभावग्रस्त थे। सदैव महंगाई, जंगल में व्याप्त भ्रष्टाचार और बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था का रोना रोते रहते। शेर यदा-कदा खरगोशों को दिलासा देने की खातिर अलग-अलग वन-क्षेत्रों में दावत पार्टियां करते थे और खरगोशों को भी आमंत्रित किया करते थे। दावत से पहले एक शेर दूसरे शेर को देखकर गुर्राने का अभिनय करता। वे आपस में पंजे लड़ाते। उठापटक करते। एक शेर दूसरे को पटक देता। दूसरा तीसरे को धूल चटा देता। खरगोश यह दृश्य देखकर आनंदित होते थे। उन्हें अपने क्षेत्र के राजा से दूसरे इलाके का राजा बेहतर प्रतीत होता था। ड्रामा समाप्त होता। दावत आरंभ होती। शेरों की पार्टी में एक हजार खरगोश आते तो उनमें से आधे ही अपने घरों को लौट पाते थे। खरगोश रोते-बिसूरते और फिर अपने कुनबों की आबादी बढ़ाने में लग लेते। वहीं कुछ खरगोश व्यवस्था परिवर्तन और क्रांति के लिए कुछ न कुछ तिकड़में भिड़ाने की जुगत में लगे रहते।

इसी सिलसिले में किसी दिन एक खरगोश के बच्चे के हाथ नीति कथाओं की एक किताब लग गई। पन्ने पलटे तो उसे कुछ काम सामग्री नजर आई। उसमें शेर और खरगोश वाली पंचतंत्र की वह कहानी भी थी, जिसमें खरगोश शेर को कुएं पर ले जाता है और उसकी परछाई दिखला कर कहता है कि महाराज, कुएं में एक और शेर है। इस तरह वह असली शेर को कुएं में छलांग लगवा देता है। कहानी के अंत में, जैसा कि पुराने समय की कहानियों में हुआ करता है, नैतिक शिक्षा दी हुई थी कि बुद्धि से बल को परास्त किया जा सकता है। उस खरगोश के बच्चे को लगा कि इसी तरह वह भी अपने क्षेत्र के राजा को हटा सकता है। वह शेर के पास जाकर बोला, 'हे महाराज, मैं आपका आहार बनना चाहता हूं। मगर उधर कुएं में एक और शेर बैठा हुआ है जो मुझे मना कर रहा है।' ऐसा कहकर खरगोश का वह बच्चा शेर को उस कुएं के पास ले जाने में सफल हो गया। शेर ने कुएं में झांका, फिर अपनी गर्दन पीछे घुमाकर खरगोश के उस शावक से बोला, 'बेवकूफ कहीं के! वहां पानी में जो बैठा है, वह मेरी परछाई नहीं, मेरा भाई है।' इतना कहकर उस शेर ने खरगोश के बच्चे को अपने पंजों में समेट लिया। कुएं का शेर भी बाहर निकल आया और फिर दोनों ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | देश में किसके कितने पेट्रोल पंप

स्रोत : तेल मंत्रालय की पेट्रोलियम योजना व विश्लेषण सेल

ऊर्जा

मन

जैसे योग, आसन और व्यायाम के बगैर मानव शरीर पुष्ट नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मन का कार्य उचित तरीके से संपन्न करने के लिए कुछ न कुछ मानसिक योग-व्यायाम भी आवश्यक हैं। जिस मानव में असीम शारीरिक शक्ति हो, लेकिन मन का स्वरूप विकसित न हो, उसे पूर्ण मनुष्य नहीं कहा जा सकता। क्या आपके मन में बीते हुए दुर्बल और हानिकारक विचार उत्पन्न होते हैं? ऐसे विचारों के लिए अंतःकरण शुद्ध कीजिए। इन्हें स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। समस्त रोग, शोक, दुख, निराशा के विचार मन में विषैले जीवाणु उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनसे मुक्त रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। मन का मैल निकाल देने पर व्यक्ति उत्तम रीति से कार्य संपन्न कर सकता है। व्यक्ति का पहला मानसिक दोष उसकी अत्यधिक चंचलता है। स्वभावतः मन चंचल है, किन्तु उसका रंग-बिरंगी तितली की भांति एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराना गलत है।

कोई तत्व, विशेष विचार या भावना को ले लीजिए। वह चाहे जैसा शुष्क क्यों न हो, उस पर मन की समग्र वृत्तियों को एकाग्र कर दीजिए। मन कुछ समय उपरांत भागेगा, किंतु आप संयम द्वारा उसे बांधे रखिए। विचलित न होइए। इस क्रिया से मन में दृढ़ता आती है। मनन करना मन का श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। आप सारे दिन किस प्रकार के विचारों का चिंतन-मनन करते हैं, किन-किन विभिन्न वृत्तियों, भावनाओं में दिन गुजारते हैं? अपने मन के दृष्टा बनकर पूर्ण परीक्षा कीजिए। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य अपने विषय में तुच्छ विचार रखता है, वह भयंकर मानसिक रोग से पीड़ित है। एक ऊंची भावना मन में लेकर उसी विषय में निमग्न होकर विचरण करें। उसी से आत्मा को स्नान कराते रहें। शुभ विचार से द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि का उद्भव नहीं होता। निरोग मन बनाने के लिए अपने ईश्वर तत्व को प्रकाशित कीजिए। आपके मन का प्रत्येक अणु ईश्वर तत्व से अनुप्राणित है। ईश्वर के मार्ग प्रकाश में अवरोध न डालिए। यदि अध्ययन, मनन या साधना के समय यदि मन को दृढ़ता से एकाग्रचित्त न किया जाए, तो उसके फल प्राप्त ही नहीं होते। अशुभ चिंतन मानसिक दुर्बलता का प्रतीक है। इससे मन की शक्तियां समाप्त होती हैं। उत्साह क्षीण होता है। आशावादिता नष्ट होती है। परिणामस्वरूप वह कोई भी अच्छा उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पाता।

डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी

बहाने की बुनियाद

राजनीति में अक्सर यह बात कही जाती है कि जीत के हजार यार होते हैं जबकि हार अनाथ होती है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे का अभी इंतजार है, लेकिन कांग्रेस के कई केंद्रीय नेता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विपरीत चुनाव नतीजे उलटे होने की आशंका जाहिर करने लगे हैं। प्रतिकूल परिणाम आने की स्थिति में इसकी जवाबदेही का सवाल हाईकमान पर भी उठे इसको लेकर पार्टी नेता अभी से सचेत हैं। शायद इसीलिए अनौपचारिक चर्चा में पार्टी नेता हिमाचल चुनाव के पूरे अभियान के दौरान एआइसीसी और सूबे के नेतृत्व के बीच समन्वय नहीं बन पाने की बातें उठा रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने आई चुनावी फंड की समस्या को भी समन्वय के अभाव का नतीजा बताया जा रहा। पार्टी हलकों में दावा किया जा रहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र ने चुनाव खर्च का जिम्मा उठाने का भरोसा दिया था, मगर बाद में फंड की दिक्कत बता केवल 30 उम्मीदवारों का खर्च उठाने की बात कही। इसमें भी कई उम्मीदवारों को पर्याप्त साधन नहीं मिल पाए। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को भेजने के मामले में भी वीरभद्र के दिलचस्पी नहीं लेने की बातें कही जा रही हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे प्रभाव रखने वाले स्टार प्रचारक भी इंतजार करते रहे मगर प्रचार के लिए खास बुलावा नहीं आया। इस कानाफूसी से साफ है कि उलटे नतीजे के लिए पार्टी में केंद्रीय स्तर पर बहाने की बिसात बिछाई जाने लगी है।

राजरंग

खुशखबरियों का सिलसिला

मोदी सरकार के सितारे लगातार बुलंदी पर हैं। हर तरफ से खुशखबरी ही सुनने को मिल रही है। शुक्रवार का दिन दो अलग-अलग मोर्चों पर खुशखबरी लेकर आया। एक तरफ यूपी स्थानीय निकाय चुनावों में भारी विजय ने सरकार को गुजरात चुनावों के लिए बूस्टर डोज दे दी। वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में भारत का दबदबा और बढ़ गया। भारत को इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर (आइएमओएचक्यू) काउंसिल में बी-कैटेगरी (अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक हिस्सेदारी रखने वाले विकासशील देश) की सीट दो साल के लिए पुनः मिल गई। चुनाव में भारत को जर्मनी के बाद सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए। जहां जर्मनी को 146 वोट मिले वहीं भारत 144 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड जैसे अन्य विकसित देशों को भारत से कम वोट मिले। अर्जेंटीना और बांग्लादेश को तो जगह ही नहीं मिली। गडकरी ने तुरंत ट्वीट कर इस कामयाबी को देशवासियों के साथ साझा किया।

किधर जाएंगे यादव

उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में समाजवादी का सूपड़ा साफ होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि इसके कोर वोटर यादव किधर जाएंगे। ऐतिहासिक जीत के बाद आत्मविश्वास से भरे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लग रहा है कि बसपा के साथ सीधे लड़ाई में रहा यादव समुदाय देर-सवेर उनके खेमे में ही आएगा। वहीं मुस्लिम वोटों के बसपा की ओर खिंचने से कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में जगह बनाना और भी मुश्किल हो गया है। चुनावी रणनीति से जुड़े नेताओं की मानें तो यादव समुदाय का भाजपा की ओर झुकाव 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, लेकिन इससे भाजपा द्वारा बड़े जतन से जुटाई गई छोटी-छोटी जातियों में खलबली मच सकती है। ऐसे में मायावती की अगली चाल अहम साबित होगी। मायावती भाजपा विरोध की धुरी बन सकती हैं और यदि इसमें सपा और कांग्रेस भी साथ आने में सफल रहीं तो भाजपा के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी।

प्रचार की लालसा

कुछ छोटे मंत्री फिर से परेशान हैं। इस बार उनकी परेशानी का सबब काम नहीं, बल्कि मीडिया में उन्हें जगह नहीं मिलना है। अपने बड़े मंत्रियों के मुकाबले कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति महत्वहीन हो जाती है, लेकिन स्वतंत्र तौर पर किसी कार्यक्रम में जाकर भी उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है। इसके चलते मंत्रालय और इन मंत्रियों का कामकाज देखने वाले स्टाफ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक छोटे मंत्री तो यहां तक कहते सुने गए हैं कि आखिर उन्हें भी प्रधानमंत्री को अपना प्रदर्शन दिखाना है। कहीं छपेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वह कैसा काम कर रहे हैं। आखिर मंत्री बने रहने के लिए इतना सब तो करना बनता ही है।

ट्वीट-ट्वीट

अर्से बाद गुजरात में भाजपा के अलावा भी कोई एजेंडा सेट कर रहा है। राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व के ट्रैप में भाजपा भी ऐसी फंसी कि अरुण जेटली को भी यह कहना पड़ा कि जब असली हिंदू पार्टी मौजूद है तो फिर क्लोन की क्या जरूरत!
अखिलेश आनंद@akhileshanandd

ईवीएम के मसले पर चुनाव आयोग कई बार पाक साफ होकर निकला है और तमाम तरह से मामले को समझाया भी है। फिर भी अगर आप इसे समझ नहीं सकते तो अपने स्कूल पर मुकदमा ठोंकिए जहां से आपने पढ़ाई की।
कंचन गुप्ता@KanchanGupta

भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को नाबाद दोहरे शतक के लिए बधाई कि इस साल उन्होंने अभी तक 200 से अधिक आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। आशा है कि एक दिन वहां शांति भी कायम होगी।
वीरेंद्र सहवाग@virendersehwag

विडंबना/विरोधाभास– रांची 'झारखंड लिटरेरी मीट' में नई हिंदी' के तीन सितारा लेखक अपनी चर्चा में बिना अंग्रेजी के एक वाक्य भी बमुश्किल बोले। तुरंत बाद के सत्र में दक्षिण भारतीय, अंग्रेजी लेखक जयराम रमेश अपनी अंग्रेजी किताब पर सुंदर और सिर्फ हिंदी में। क्या है यह? क्यों है?
राहुल देव@rahuldev2

जनपथ

धारो यज्ञोपवीत अब है फैशन की बात,
जाने नहीं त्रिसूत्र यह निज धारक की जात।
निज धारक की जात चलो दिन इसके बहुरे,
वोटबैंक पर आज नाचते दिखते भंवरे।
बना जनेऊ ब्रांड पहन कर शान बघारो,
पहन सूट थ्री पीस जनेऊ उसपर धारो।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।